

आयकर आयुक्त,अहमदाबाद

बनाम

इक्विनॉक्स सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड

(2007 की सिविल अपील संख्या 4399)

18 अप्रैल 2017

[आर.के. अग्रवाल, अभय मनोहर सप्रे, जे. जे.]

सिविल अपील संख्या 4399/2007

आयकर अधिनियम 1961 -एसएस 50(2), 48(2) - प्रयोज्यता - संपत्ति और देनदारियों के साथ चल रहे व्यवसाय की एक बार में बिक्री यदि "दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति" की प्रकृति में मंती की बिक्री के रूप में मानना - उत्तरदाता- निर्धारिती ने संपूर्ण चल रहा व्यवसाय एक ही बार में बेच दिया और ऐसी बिक्री को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति में मंती की बिक्री के रूप में धारा 48(2) के तहत निर्धारित कटौती मानना - मूल्यांकन अधिकारी ने दावा की गई छूट को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि निर्धारिती का मामला धारा 50(2) के तहत कवर किया गया था क्योंकि यह अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति में था - सीआईटी (अपील) के समक्ष प्रतिवादी द्वारा अपील, यह मानने की अनुमति देती है कि उपक्रम स्वयं एक पूंजीगत संपत्ति थी, जिसका स्वामित्व उत्तरदाता के

पास छह साल के लिए था, जो लंबी अवधि की प्रकृति में पूंजीगत संपत्ति था और उसे चालू संस्था के रूप में एक ही बार में बेच दिए जाने को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ नहीं कहा जा सकता है - राजस्व द्वारा अपील, आईटीएटी और उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई - अपील पर, माना गया: प्रतिवादी का मामला धारा 50(2) के अंतर्गत नहीं आता है - धारा 50(2) के प्रावधान उस मामले पर लागू होंगे जहां निर्धारिती संपत्ति के एक या अधिक ब्लॉक को स्थानांतरित करता है, जिसका उपयोग वह अपने व्यवसाय को चलाने में कर रहा था - हालाँकि, जब संपूर्ण चल रहा व्यवसाय सभी संपत्तियां और देनदारियां एक बार में बेची जाती हैं, जैसा कि उत्तरदाता द्वारा किया गया था, यह "दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति" की मंदा बिक्री है, न कि "अल्पकालिक पूंजीगत संपत्ति" की - इसलिए, इस पर तदनुसार कर लगाया जाना आवश्यक था- तर्क में कोई गलती नहीं पाई गई और सीआईटी (अपील) द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय ने उचित रूप से सही ठहराया।

अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया की

1. उत्तरदाता (निर्धारिती) का मामला आयकर अधिनियम की धारा 50(2) की परिसीमा के अंतर्गत नहीं आता है। धारा 50(2) उस मामले पर लागू होती है जहां परिसंपत्तियों का ब्लॉक निर्धारिती द्वारा स्थानांतरित किया जाता है,-लेकिन जहां परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ पूरा चल

रहा व्यवसाय निर्धारिती द्वारा एक बार में बेच दिया जाता है, ऐसी बिक्री को "अल्पकालिक पूंजीगत संपत्ति" के रूप में नहीं माना जा सकता है। ". दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 50(2) के प्रावधान उस मामले पर लागू होंगे जहां निर्धारिती संपत्ति के एक या अधिक ब्लॉक को स्थानांतरित करता है, जिसका उपयोग वह अपने व्यवसाय को चलाने में कर रहा था। यहां ऐसा मामला नहीं है क्योंकि इस मामले में, निर्धारिती ने पूरा व्यवसाय एक चालू संस्था के रूप में बेच दिया। [पैरा 11][97-ई-एफ]

आयकर आयुक्त, गुजरात बनाम आर्टेक्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी
1997 (6) एससीसी 437 सीआईटी: [1997] 1 सप्ल। एससीआर 608 - पर
निर्भर।

प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी और अन्य
264 आईटीआर 193 (बॉम्बे) - अनुमोदित।

केस कानून संदर्भ

[1997] 1 सप्ल एससीआर 608 पर निर्भर

पैरा 13

264 आईटीआर 193 (बॉम्बे) अनुमोदित

पैरा 14

सिविल अपील क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 4399/2007

2003 की आयकर अपील संख्या 59 में गुजरात उच्च न्यायालय
अहमदाबाद के निर्णय और आदेश दिनांक 29-7-2003 से

के. राधाकृष्णन, सीनियर अधिवक्ता, रूपेश कुमार, श्वेता गर्ग (फॉर
श्रीमती अनिल कटियार)- अधिवक्तागण प्रार्थी की और से

इन्दर पॉल बंसल, विवेक बंसल, हरेश रायचुरा, सरोज रायचुरा-
अधिवक्तागण अप्रार्थी की और से

न्यायाधिपति अभय मनोहर सप्रे, द्वारा न्यायालय का निर्णय
सुनाया गया

न्यायाधिपति अभय मनोहर सप्रे.

(1) यह अपील राजस्व (आयकर विभाग) द्वारा गुजरात उच्च
न्यायालय अहमदाबाद द्वारा 2003 के आईटीए संख्या 59 में पारित आदेश
दिनांक 29.07.2003 के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत उच्च
न्यायालय ने राजस्व की अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि
अपील में आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप
में संदर्भित) की धारा 260-ए के तहत कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न
शामिल नहीं है ।

(2) हमने इस अपील में शामिल मुद्दों की विवेचना करने के लिए
संक्षेप में तथ्य प्रस्तुत किए हैं।

3) उत्तरदाता - निर्धारिती अहमदाबाद में सीआरपीए और ओपी शेड से शीट मेटल घटकों के निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ था। प्रतिवादी ने अपना पूरा चल रहा व्यवसाय एक बार में बेचने का फैसला किया। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी ने अपना पूरा चल रहा व्यवसाय अपनी सभी संपत्तियों और देनदारियों के साथ 31.12.1990 को "एमट्रेक्स एप्लायंसेज लिमिटेड" नामक कंपनी को 58,53,682/- रुपये में विक्रय कर दिया।

4) उत्तरदाता ने निर्धारण वर्ष 1991-1992 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया। रिटर्न में, उत्तरदाता ने निर्धारिती के हाथ में बिक्री को चल रही चिंता की "मंदी बिक्री" की प्रकृति में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति में मानते हुए। अधिनियम की धारा 48 (2) के तहत कटौती का दावा किया, जैसा कि तब था।

(5) निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 04.03.1994 द्वारा कटौती का दावा करने में निर्धारिती के तर्क को स्वीकार नहीं किया। मूल्यांकन अधिकारी के अनुसार, निर्धारिती का मामला अधिनियम की धारा 50 (2) के तहत कवर किया गया था क्योंकि यह अधिनियम की धारा 50 (2) में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति में था और इसलिए इस अधिनियम की धारा 48 (2) अंतर्गत नहीं आता था। जैसा कि निर्धारिती द्वारा दावा किया गया है। मूल्यांकन अधिकारी ने तदनुसार

कटौती के दावे को अधिनियम की धारा 50 (2) के तहत आने वाला मानते हुए फिर से काम किया और मूल्यांकन आदेश तैयार किया।

(6) निर्धारिती ने व्यथित महसूस करते हुए सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की। आदेश दिनांक 06.10.1995 द्वारा, अपील आयुक्त ने निर्धारिती की अपील को अनुमति दे दी, जहां तक यह कटौती के मुद्दे से संबंधित थी। उन्होंने कहा कि जब यह एक निर्विवाद तथ्य है कि निर्धारिती ने अपना पूरा चल रहा व्यवसाय अपनी संपत्ति और देनदारियों के साथ एक ही बार में मंदा की कीमत पर बेच दिया है और इसलिए, अधिनियम की धारा 50 (2) के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसी बिक्री. उन्होंने कहा कि यह किसी व्यक्ति या एक ब्लॉक संपत्ति की बिक्री का मामला नहीं है, जिस पर अधिनियम की धारा 50 (2) के प्रावधान लागू हो सकते हैं। इसके बाद उन्होंने "दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ" और "अल्पकालिक पूंजीगत संपत्ति" की परिभाषा के संदर्भ में निर्धारिती के मामले की जांच की और माना कि चूंकि उपक्रम स्वयं एक पूंजीगत संपत्ति है, जिसका स्वामित्व लगभग छह वर्षों से निर्धारिती के पास है और वह इसमें शामिल है। लंबी अवधि की पूंजीगत संपत्ति की प्रकृति और उसे चालू संबंध में एक ही बार में बेच दिया गया है, इसे "अल्पावधि पूंजीगत लाभ" नहीं कहा जा सकता है ताकि अधिनियम की धारा 50 (2) के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके । निर्धारण अधिकारी. सीआईटी (अपील) ने तदनुसार निर्धारिती को कटौती का दावा

करने की अनुमति दी जैसा कि उन्होंने मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष दावा किया था।

7) सीआईटी (अपील) के आदेश से व्यथित राजस्व ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की। आदेश दिनांक 27.06.2002 द्वारा, ट्रिब्यूनल अपील आयुक्त के तर्क और निष्कर्ष से सहमत हुआ और तदनुसार राजस्व की अपील को खारिज कर दिया।

8) ट्रिब्यूनल के आदेश से व्यथित राजस्व ने अधिनियम की धारा 260-ए के तहत आगे की अपील में मामले को उच्च न्यायालय में ले जाया। आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपील में अधिनियम की धारा 260-ए के अर्थ के भीतर कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है। इस आदेश के विरुद्ध राजस्व ने व्यथित महसूस किया और मामले को विशेष अनुमति के माध्यम से अपील में इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

9) अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. राधाकृष्णन और प्रतिवादी-निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता श्री इंदर पॉल बंसल को सुना।

10) उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, सीआईटी (अपील) द्वारा अपने आदेश में दिए गए तर्क और निष्कर्ष में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है, जो हमारे

विचार से सही था। ट्रिब्यूनल द्वारा और फिर उच्च न्यायालय द्वारा इस अपील में इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किए जाने को बरकरार रखा गया।

11) हमारी सुविचारित राय में, प्रतिवादी (निर्धारिती) का मामला अधिनियम की धारा 50 (2) के परिसीमा के अंतर्गत नहीं आता है। धारा 50 (2) उस मामले पर लागू होती है जहां परिसंपत्तियों का कोई भी ब्लॉक निर्धारिती द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, लेकिन जहां परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ पूरा चल रहा व्यवसाय निर्धारिती द्वारा एक बार में बेच दिया जाता है, ऐसी बिक्री, हमारे विचार में, अल्पकालिक पूंजीगत संपत्ति "के रूप में "नहीं" मानी जा सकती है। दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 50 (2) के प्रावधान उस मामले पर लागू होंगे जहां निर्धारिती संपत्ति के एक या अधिक ब्लॉक को स्थानांतरित करता है, जिसका उपयोग वह अपने व्यवसाय को चलाने में कर रहा था। यहां ऐसा मामला नहीं है क्योंकि इस मामले में, निर्धारिती ने पूरा व्यवसाय एक चालू संस्था के रूप में बेच दिया।

12) जैसा कि सीआईटी (अपील) ने सही ढंग से देखा है कि सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ पूरा चल रहा व्यवसाय प्रतिवादी-निर्धारिती द्वारा एक बार में बेच दिया गया था, यह "दीर्घकालिक पूंजीगत

संपत्ति" की मंती की बिक्री थी। इसलिए, इस पर तदनुसार कर लगाया जाना आवश्यक था।

13) हमारे विचार को आयकर आयुक्त, गुजरात बनाम आर्टेक्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून से समर्थन मिलता है । [1997(6) एससीसी 437 सीआईटी]।

14) प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी एवं अन्य , 264 आईटीआर 193 (बॉम्बे) में भी, बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कुछ इसी तरह के तथ्यों पर इस प्रश्न की विस्तार से जांच की और वही दृष्टिकोण अपनाया है। विद्वान न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया - (उनकी नियुक्ति तब बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में थी और बाद में सी.जे.आई बने) ने बेंच के लिए बोलते हुए उस कानूनी स्थिति को उपयुक्त रूप से समझाया जिससे हम सहमत हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे तथ्यों पर लागू कानूनी स्थिति को सही ढंग से संक्षेप में प्रस्तुत किया है।

15) अपीलकर्ता (राजस्व) के लिए विद्वान अधिवक्ता विपरीत दृष्टिकोण रखते हुए किसी भी निर्णय का हवाला देने में सक्षम नहीं थे और न ही वह निर्धारिती के अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त संदर्भित बार में उद्धृत निर्णयों में कोई त्रुटि इंगित करने में सक्षम थे।

16) पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हमें अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है जो विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज की जाती है।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अनीश दाधीच द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।